(i) परिसम्पत्ति का पुनर्निर्माण और स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देना।

(ii) बेरोजगार हुए कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण; और

(iii) बन्द मिलों की परिसम्पत्तियों का उपयोग।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता राशि संबंधी स्वीकृति से संबंधित संचालनात्मक कार्य पूरा हो जाने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

श्रमिकों की समस्याओं संबंधी त्रिपक्षीय समिति का प्रतिवेदन

5899. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपक्षीय समिति ने श्रमिकों की समस्याओं से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ख) श्रम संबंधी नई औद्योगिक नीति के प्रभाव और अन्य संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्रम मंत्रालय ने 12 नवम्बर, 1991 को एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया था। 21.12.93 को आयोजित समिति की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि उन उद्योगों जिनमें रुग्णता बार-बार हो जाती है, से संबंधित त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि वे उपचारात्मक और निवारात्मक उपायों का सुझाव दें।

विशेष त्रिपक्षीय समिति के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित छः औद्योगिक समितियों को पुनर्जीवित किया गया जिनके नाम हैं: सूती कपड़ा, जूट, रसायन, इंजीनियरी, विद्युत (उत्पादन और संवितरण) और सड़क परिवहन संबंधी औद्योगिक समिति।

विशेष त्रिपक्षीय समिति और छः औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां रुग्णता, औद्योगिक पुनर्संरचना से संबंधित विषयों तथा कर्मकारों की समस्याओं से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करती रही है। उनकी सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों को यथासमय सूचित कर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

Construction of Central Board for Workers Education Headquarters

5900. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) when did the foundation stone of Central Board for Workers Education Headquarters was laid down;

(b) what was the estimated cost of the building;

(c) whether the construction took place, if so, when and what is the present stage in which the work is pending;

(d) by when it will be over;

(e) what will be its cost then; and

(f) who is responsible for any delay with regard to this project and what action is being taken against him?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) to (f) The foundation stone of the Central Board for Workers' Education Headquarters building was laid on 2.8.1990. The CPWD initially estimated the cost of its construction at Rs. 127.88 lakhs. The construction commenced in December 1991 and the possession of the building has been taken over the April, 1995. The construction has been completed at a cost of Rs. 213.29 lakhs. The escalation in the cost of construction is on account of construction of additional area and increase in the cost of construction index.

Recommendations of Sub-Committee of the Consultative Committee

5901. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state that the response of Government to the recommendations of the Sub-Committee of the Consultative Committee of Ministry of Labour on Provident Fund default?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): The recommendations of the Committee relating to setting up of special police Cell by State Governments strengthening of supervision on exempted establishments, computerisation etc have been accepted and forwarded to the concerned authorities for implementation. The remaining recommendations involve consultation with other Ministries/Departments and in some cases also amendment of the Act. As such at present it is difficult to indicate the response of the Government about them.

Recommendation of the National Commission on Rural Labour

5902. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state the response of Government to the recommendations of the National Commission on Rural Labour?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): The Action Taken Report on the recommendations of the National Commission on Rural Labour *inter-alia* reflecting Government response to all major recommendations has already been laid on the Table of the House on 3.2.93 in fulfilment of Assurance given during Short Duration Discussion on 4.8.92.

Special assistance from central assistance fund for Rajasthan and Orissa

5903. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Central Government to allocate special assistance from the Central Assistance Fund under the Special Assistance Plan during the Eighth Plan period to solve the basic problems of the big cities of the Rajasthan and Orissa;

(b) if so, the measures taken by Government in this regard;

(c) whether State Government have made any demand in this regard during the current year, if so, the reaction of Government thereto; and

(d) by when Government will allocate the assistance for the above purpose to Rajasthan and Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Governments of Rajasthan and Orissa have not made any demand for special Plan assistance during the current year for solving the basic problem of big cities in their States.

(d) Does not arise.

बिहार में पिछड़ेपन और बेरोजगारी को समाप्त किया जाना

5904. **श्री आस मोहम्मद:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) से (घ) राज्य की विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई विकास स्कीमों के निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से जिम्मेवार हैं। इस प्रकार अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रों के विकास के लिए गति